

ऐतिहासिक रूप से, भारत जलवायु न्याय का प्रबल समर्थक रहा है।

अगले पखवाड़े में, जलवायु संकट के समाधान के लिए बेताब दुनिया दो साल पहले हुई बैठक की तुलना में ग्लासगो में युनाइटेड नेशनस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस (यूएनएफसीसीसी) की पार्टियों के 26वें सम्मेलन से बहुत बेहतर परिणाम की उम्मीद कर रही होगी। मैड्रिड में COP-25 की विफलता से सब परिचित है।

पिछले साल मैड्रिड सम्मेलन कोविड-19 महामारी के कारण आयोजित नहीं किया गया था। लगभग दो दिनों तक ओवरटाइम जाने के बावजूद पेरिस संधि के नियमों को संहिताबद्ध करने की जद्दोजहद वैश्विक जलवायु कूटनीति को समन्वय युक्त बनाने और जीएचजी उत्सर्जन को कम करने की अनिवार्यता के बीच एक संबंध में दूरी को दर्शाती है। यूएनएफसीसीसी के इतिहास में सबसे लंबी बैठक के भूतों को भगाने के लिए कार्बन बाजारों के भविष्य को लेकर भारत, चीन और ब्राजील और औद्योगिक देशों के बीच गतिरोध को तोड़ने की आवश्यकता होगी।

उत्तरार्द्ध ने पूर्व-पेरिस संधि युग में अर्जित कार्बन क्रेडिट को ऐतिहासिक सौदे की नियम पुस्तिका में बदलने की अनुमति देने के प्रयासों को रोक दिया है, यह दावा करते हुए कि इनमें से कई क्रेडिट उत्सर्जन में कमी का सटीक प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। मैड्रिड में जो तकरार देखी गयी वह इस दिशा में प्रयासों के एक नए निम्न का प्रतिनिधित्व करती है। विकसित दुनिया लगातार जिस प्रकार से अपनी वित्तीय, तकनीकी और उत्सर्जन से संबंधित प्रतिबद्धताओं पूरा करने में जिस प्रकार से विफल रही है उसके कारण अविश्वास बढ़ता जा रहा है।

हालाँकि, दिसंबर 2019 के बाद से यह माँग करने के लिए बहुत कुछ हुआ है कि ग्लासगो में वार्ताकार मैड्रिड के अधूरे कार्यों को पूरा करने से ज्यादा कुछ करें। मौसम अधिक अप्रत्याशित हो गया है, महामारी ने स्वास्थ्य और पर्यावरण के बीच बिंदुओं को जोड़ना आवश्यक कर दिया है और दुनिया एक ऊर्जा संकट से घिरी हुई है। अगस्त में, आईपीसीसी की एक रिपोर्ट ने चेतावनी दी थी कि अगले दो दशकों में ग्रह 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक गर्म हो सकता है, भले ही राष्ट्रों ने उत्सर्जन में तुरंत कटौती करना शुरू कर दिया हो। इन सख्त चेतावनियों ने उत्सर्जन में कटौती के लिए पेरिस संधि के स्वैच्छिक तंत्र, जिसे राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) के नाम से जानते हैं, पर ध्यान केंद्रित किया है।

एनडीसी की हमेशा पूर्व-औद्योगिक युग की तुलना में 2 डिग्री से अधिक तापमान वृद्धि को रोकने के लिए संचयी रूप से अपर्याप्त होने के लिए आलोचना की गई है। अब, प्रलयकारी तापमान वृद्धि की आशंका बहुत पहले से थी, विकसित देशों- अमेरिका के नेतृत्व में, जिसने राष्ट्रपति बिडेन के तहत पेरिस संधि में फिर से प्रवेश किया है - ने अधिक वैश्विक जलवायु महत्वाकांक्षा के लिए अपने पहले के आह्वान को बढ़ाना शुरू कर दिया है।

काँप-26 के लिए अधिकांश चर्चाओं में सभी देशों द्वारा 2050 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध होने की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित किया गया है। विकसित और विकासशील देशों के बीच कार्बन तटस्थता एक विवादास्पद विषय बना हुआ है, भले ही लगभग 130 देशों ने इसके लिए अलग-अलग प्रतिबद्धताएं की हैं। संयुक्त राष्ट्र की जलवायु प्रक्रिया की विश्वसनीयता इस बात पर निर्भर करती है कि यह वैश्विक जीएचजी उत्सर्जन में कटौती की महत्वपूर्ण आवश्यकता के साथ भारत जैसे देशों द्वारा विकास के सही दावों को कैसे संतुलित करती है।

ऐतिहासिक रूप से, भारत जलवायु न्याय का प्रबल समर्थक रहा है। देश के वार्ताकारों को अपने विकास के स्थान को नहीं छोड़ने में दृढ़ रहना चाहिए। आखिरकार, भारत अपने पेरिस लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में अग्रसर है।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

प्र. काँप-26 वार्ता निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित होगी?

- (a) शंघाई
- (b) ग्लासगो
- (c) कोपेनहेगन
- (d) मास्को

Expected Question (Prelims Exams)

Q. In which of the following places will the COP-26 talks be held?

- (a) Shanghai
- (b) Glasgow
- (c) Copenhagen
- (d) Moscow

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. विकसित देशों एवं विकासशील देशों के मध्य जलवायु परिवर्तन को लेकर क्या विवाद विद्यमान है? विकसित देशों के द्वारा जलवायु परिवर्तन को लेकर क्या अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है? (250 शब्द)

Q. What is the dispute between developed countries and developing countries regarding climate change? What more efforts need to be done by the developed countries regarding climate change? (250 Words)

नोट :- अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रख कर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।